

गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 197
दि. 18.11.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
AHMEDABAD EDITION

नई ग्रामीण रोजगार योजना से राज्यों की बढ़ेगी वित्तीय मुश्किलें

मनरेगा के मुकाबले छह गुना अधिक खर्च का अनुमान, राज्यों पर पड़ सकता है 33 हजार करोड़ रुपये का बोझ; उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त 2 से 3 हजार करोड़ रुपये तक जुटाने पड़ सकते हैं

नई दिल्ली। ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने वाली नई योजना 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जी रामजी को लेकर राज्यों के सामने वित्तीय चुनौती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यदि यह नई योजना वित्त वर्ष 2025-26 में मनरेगा की जगह लागू होती, तो राज्यों को करीब 33 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते। इसके मुकाबले मनरेगा के तहत राज्यों का वास्तविक खर्च केवल 5,261 करोड़ रुपये रहा था। इस तरह नई व्यवस्था में राज्यों का खर्च लगभग छह गुना अधिक होता। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों पर ही 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान जताया गया है। यह आकलन बताता है कि ग्रामीण रोजगार की गारंटी बढ़ाने के साथ ही राज्यों की जिम्मेदारी और वित्तीय हिस्सेदारी भी काफी बढ़ने वाली है। पीआरएस ने अपनी 'स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2026-27' में नई ग्रामीण रोजगार योजना के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च को आधार बनाकर यह अनुमान लगाया गया है कि यदि उसी वर्ष वीबी-जी रामजी लागू होती, तो राज्यों को कितनी राशि खर्च करनी पड़ती। इस गणना में समान रोजगार दिवस और मजदूरी दरों को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्च बांटने का तरीका बदलने से राज्यों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होती। यही वजह है कि मनरेगा के तहत अपेक्षाकृत कम राशि खर्च करने वाले राज्यों को नई व्यवस्था में कहीं अधिक बजट जुटाना पड़ सकता है। नई योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्च का अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि योजना पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना होगा। हालांकि, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 90:10 रखी गई है। इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि केंद्र सरकार का योगदान राज्यों के लिए निर्धारित आवंटन तक सीमित रहेगा। यदि किसी राज्य में रोजगार की मांग बढ़ने या अन्य कारणों से निर्धारित केंद्रीय आवंटन से अधिक खर्च होता है, तो अतिरिक्त राशि की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार को उठानी होगी। इससे उन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है, जहां



ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग अधिक रहती है। मनरेगा की पुरानी व्यवस्था में रोजगार की मांग के आधार पर योजना का संचालन होता था और केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार खर्च में बड़ी हिस्सेदारी केंद्र वहन करता था। नई व्यवस्था में राज्यवार आवंटन तय होने और उससे अधिक खर्च का बोझ राज्यों पर आने से वित्तीय योजना बनाना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसी राज्य में यदि सूखा, बाढ़, कृषि संकट या रोजगार के अन्य अवसरों में कमी के कारण ग्रामीण मजदूरों की मांग बढ़ती है, तो अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य को अपने बजट से अधिक धन जुटाना पड़ सकता है। इस कारण नई योजना का वास्तविक वित्तीय प्रभाव केवल तय आवंटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार की मांग और मजदूरी दरों पर भी निर्भर करेगा।

रिपोर्ट में बड़े राज्यों के लिए अतिरिक्त खर्च का अलग से उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, यदि 2025-26 में नई योजना लागू होती, तो उत्तर प्रदेश को करीब 2,943 करोड़ रुपये, बिहार को लगभग 2,573 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2,406 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को करीब 2,155 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता। ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण आबादी और रोजगार की मांग के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्यों को नई व्यवस्था में अपने बजट का बड़ा हिस्सा रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखना होगा। इन राज्यों में ग्रामीण परिवारों की बड़ी संख्या मनरेगा जैसी योजनाओं पर निर्भर रही है। ऐसे में योजना के वित्तीय ढांचे में बदलाव का असर राज्य सरकारों की अन्य विकास योजनाओं और बजटीय प्राथमिकताओं पर भी पड़ सकता है। नई योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव भी राज्यों के खर्च को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने वीबी-जी रामजी के तहत न्यूनतम मजदूरी दर 300 रुपये प्रतिदिन अधिसूचित की थी। इसके बाद राज्यों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की। पीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, यदि नई मजदूरी दरों को आधार बनाया जाए, तो राज्यों का खर्च मनरेगा के तहत 2025-26 में हुए वास्तविक खर्च की तुलना में करीब सात गुना तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि छह गुना खर्च का अनुमान भी नई मजदूरी दरों के प्रभाव को शामिल करने पर और बढ़ सकता है। मजदूरी दर जितनी अधिक होगी, उतने ही रोजगार दिवस उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को अधिक धन की आवश्यकता होगी।

नई योजना में रोजगार की गारंटी को भी बढ़ाया गया है। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी दी जाती थी, जबकि वीबी-जी रामजी में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पहली नजर में यह बदलाव ग्रामीण मजदूरों के लिए राहत और अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला दिखाई देता है। हालांकि, पीआरएस की रिपोर्ट इस बात की ओर भी ध्यान दिलाती है कि रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने से सरकारी खर्च में भी वृद्धि होगी। यदि अधिक परिवारों को लंबे समय तक काम मिलता है, तो मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र और राज्य दोनों को अधिक संसाधन जुटाने होंगे। चूंकि नई व्यवस्था में राज्यों की हिस्सेदारी पहले से अधिक है, इसलिए रोजगार दिवस बढ़ने का वित्तीय असर राज्यों पर भी पड़ेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्येक परिवार को औसतन केवल 43 दिन का रोजगार मिला था, जबकि योजना में 100 दिन काम की गारंटी थी। इसी अवधि में महज चार प्रतिशत परिवार ही पूरे 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सके। यह आंकड़ा बताता है कि कानूनी रूप से उपलब्ध रोजगार की गारंटी और वास्तविक रूप से मिले काम के बीच काफी अंतर रहा है। ऐसे में नई योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी लागू होने के बावजूद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने परिवार वास्तव में इतने दिन काम हासिल कर पाते हैं। यदि रोजगार की उपलब्धता और मांग में वृद्धि होती है, तो राज्यों को इसके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी होगी। पीआरएस ने यह भी संकेत दिया है कि नई योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली राशि के निर्धारण में राज्यों के वित्तीय आवंटन से जुड़े मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। योजना के मसौदा नियमों के अनुसार, राज्यों की हिस्सेदारी 16वें वित्त आयोग के वित्तीय आवंटन के मानकों पर आधारित होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2026-27 के केंद्रीय बजट आवंटन को आधार बनाकर किए गए आकलन के अनुसार, छह राज्यों को 2025-26 में केंद्रीय निधि की संभावित जरूरत के मुकाबले कमी का सामना करना पड़ सकता था। ऐसी स्थिति में निर्धारित केंद्रीय सहायता से अधिक खर्च राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से पूरा करना पड़ता। योजना के दूसरे वर्ष से केंद्रीय आवंटन को प्रदर्शन से जुड़े मानकों के साथ जोड़ने का प्रावधान भी चर्चा में है। इनमें मजदूरी का समय पर भुगतान जैसे मानक शामिल हैं। इसका अर्थ है कि राज्यों को केवल रोजगार उपलब्ध कराने और खर्च का हिसाब रखने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता और निर्धारित शर्तों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। यदि किसी राज्य का प्रदर्शन तय मानकों के अनुरूप नहीं रहता है, तो उसे मिलने वाली केंद्रीय सहायता प्रभावित हो सकती है। इससे राज्यों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, भुगतान प्रणाली और निगरानी तंत्र को मजबूत करना जरूरी हो जाएगा। हालांकि, नई योजना के नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम व्यवस्था के तहत राज्यों को आवंटन का आधार मनरेगा के दौरान वर्ष 2024-25 में जारी की गई राशि को बनाया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य नई योजना के शुरुआती चरण में राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। लेकिन दीर्घकाल में राज्यों की वास्तविक वित्तीय जिम्मेदारी योजना के अंतिम नियमों, निर्धारित आवंटन, मजदूरी दरों और रोजगार की मांग पर निर्भर करेगी। ग्रामीण रोजगार योजनाएं केवल मजदूरी उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने, गरीब परिवारों की आय को सहारा देने और संकट के समय आजीविका का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

आतंकियों के मददगार नेटवर्क की तह तक पहुंचेगी एनआईए

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध सामने आने की बात कही गई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद उपलब्ध कराने वाला यह तंत्र उनके लिए सुरक्षित ठिकाने, आवाजाही के रास्ते और आवश्यक संसाधन जुटाने में भूमिका निभा रहा था। मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, एनआईए ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला अपने हाथ में लिया है। एजेंसी अब इस नेटवर्क की संरचना, इसके संचालन के तरीके और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल करेगी। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा इस तंत्र में कौन-कौन लोग शामिल हैं और क्या इसके तार सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के संचालकों या उनके स्थानीय संपर्कों से जुड़े हुए हैं। एजेंसी यह भी जांच करेगी कि आतंकियों को किस तरह की सहायता दी जाती थी और इसके लिए धन, सामान तथा अन्य संसाधनों की



व्यवस्था कहां से होती थी।

इस नेटवर्क का खुलासा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सितंबर में राजौरी जिले में की गई कार्रवाई के दौरान किया था। पुलिस ने इस मामले में जाकिर हुसैन और मोहम्मद आजम को गिरफ्तार किया था। शुरुआती जांच में दोनों पर आतंकियों को ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने, उनके आवागमन के लिए रास्तों की जानकारी देने और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का आरोप सामने आया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों की भूमिका केवल सामान्य मदद तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन पर आतंकियों को छिपाने और उनके लिए आवश्यक सामान जुटाने में सहयोग करने का भी संदेह है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि किसी भी आतंकी संगठन के लिए स्थानीय स्तर पर मददगारों का नेटवर्क उसकी गतिविधियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जंगलों, पहाड़ी इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में सक्रिय आतंकियों को लंबे समय तक छिपे रहने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के लिए स्थानीय सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे नेटवर्क के माध्यम से उन्हें भोजन, ठहरने की जगह, जरूरी सामान और सुरक्षित आवागमन से संबंधित जानकारी मिल सकती है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के साथ-साथ उनके मददगारों और संपर्क सूत्रों पर भी विशेष निगरानी रखती हैं। एनआईए अब यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि राजौरी में पकड़े गए दोनों आरोपियों का संपर्क किन लोगों से था। उनके मोबाइल फोन, डिजिटल गतिविधियों, संचार माध्यमों, वित्तीय लेनदेन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के जरिए नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि क्या आरोपियों ने पहले भी किसी आतंकी को आश्रय या अन्य सहायता उपलब्ध कराई थी। एजेंसी यह पता लगाने पर भी ध्यान देगी कि इस नेटवर्क का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा था या इसके पीछे किसी बड़े संगठन की योजना और निर्देश काम कर रहे थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मामला एनआईए को सौंपे जाने के बाद जांच का दायरा बढ़ने की संभावना है। स्थानीय पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के साथ-साथ अब राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सुरक्षा सूचनाओं और अन्य एजेंसियों से मिले इनपुट का भी विश्लेषण किया जा सकता है। यदि जांच में दूसरे जिलों या राज्यों में फैले संपर्कों के प्रमाण मिलते हैं, तो उन कड़ियों की भी पड़ताल की जाएगी। एजेंसी का प्रयास होगा कि नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों, संपर्क व्यवस्था और आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों की पूरी जानकारी जुटाई जाए।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से आतंकियों के साथ उनके स्थानीय मददगारों के नेटवर्क को भी निशाने पर रख रही हैं। किसी आतंकी की मौजूदगी की सूचना जुटाने से लेकर उसे सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने तक, मददगारों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में राजौरी में सामने आए इस मामले को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से देख रही हैं। फिलहाल जाकिर हुसैन और मोहम्मद आजम इस मामले में गिरफ्तार आरोपी हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंधों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। एनआईए की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कितने लोग सक्रिय थे और जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को मदद पहुंचाने के पीछे किस स्तर की साजिश काम कर रही थी।

आईपीएल में अब नहीं दिखेगा धौनी का हेलीकॉप्टर शॉट

चेन्नई। क्रिकेट की दुनिया में अपनी शांत सोच, बेजोड़ कप्तानी और आखिरी गेंद तक मुकाबला करने के अंदाज से करोड़ों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले महेंद्र सिंह धौनी का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बतौर खिलाड़ी सफर समाप्त हो गया है। क्रिकेट के 'कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर धौनी ने 19 साल तक आईपीएल में खेलने के बाद संन्यास लेने का फैसला किया है। चेन्नई सुपरकिंग्स ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए उन्हें टीम का मेंटर नियुक्त किया है। अब वह आईपीएल 2027 से खिलाड़ी के बजाय मार्गदर्शक की भूमिका में टीम के साथ जुड़े रहेंगे। इस फैसले के साथ ही आईपीएल के उस दौर का अंत हो गया, जिसमें धौनी की मौजूदगी मैदान पर उतरते ही मुकाबले का माहौल बदल देती थी।

45 वर्षीय धौनी ने अपने आईपीएल करियर में कुल 19 साल तक खेला। इनमें से 17 साल वह चेन्नई सुपरकिंग्स की जर्सी में मैदान पर उतरे, जबकि दो सीजन उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए खेले। चेन्नई की टीम पर दो साल का प्रतिबंध लगने के कारण उन्हें पुणे की टीम का हिस्सा बनना पड़ा था। इसके बाद जब चेन्नई की वापसी हुई, तो धौनी फिर अपनी पुरानी टीम के साथ जुड़ गए। उन्होंने लंबे समय तक टीम की कप्तानी की और उसे आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में



शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। अब टीम प्रबंधन ने उन्हें मेंटर की जिम्मेदारी देकर यह साफ कर दिया है कि उनका चेन्नई से रिश्ता खिलाड़ी के रूप में संन्यास के बाद भी बना रहेगा।

धौनी का संन्यास लेने का अंदाज भी उनके व्यक्तित्व की तरह शांत और सहज रहा। न कोई बड़ा समारोह, न लंबी भावुक घोषणा और न ही मैदान पर विदाई मैच की मांग। चेन्नई सुपरकिंग्स की सह-मालिक रूपा गुरुनाथ ने बताया कि 2027 सीजन के लिए खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखने और रिलीज करने को लेकर शनिवार को वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा हो रही थी। टीम प्रबंधन खिलाड़ियों की सूची पर विचार कर रहा था। इसी दौरान जब प्रबंध निदेशक के.एस. विश्वनाथन रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों के नाम पढ़ रहे थे, तब धौनी ने बेहद धीमे अंदाज में कहा कि शायद इस सूची में उनका नाम भी जोड़ देना चाहिए। रूपा गुरुनाथ के मुताबिक, धौनी की यह बात सुनकर वीडियो कॉल अचानक समाप्त हो गई। उनका यह छोटा-सा वाक्य ही उनके आईपीएल करियर के अंत का संकेत बन गया।

चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने आधिकारिक संदेश में धौनी को टीम का मेंटर बनाए जाने की घोषणा की। फ्रेंचाइजी ने कहा कि धौनी की यात्रा अनगिनत जीत, कठिन दौर और ऐसी यादों से भरी रही है, जो हमेशा प्रशंसकों के दिलों में रहेंगी। टीम के मालिक एन. श्रीनिवासन ने भी धौनी के योगदान को याद करते हुए कहा कि चेन्नई सुपरकिंग्स की पहचान और उसका घर हमेशा धौनी से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में धौनी को टीम से जोड़ने का उनका फैसला सबसे अच्छे फैसलों में से एक रहा। उनके अनुसार, धौनी ने केवल मैदान पर उपलब्धियां हासिल नहीं कीं, बल्कि अपने व्यवहार, नेतृत्व और व्यक्तित्व से टीम के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया, जो वर्षों तक कायम रहेगा।

धौनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता। टीम ने वर्ष 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा धौनी ने चेन्नई को दो बार चैंपियंस लीग टी-20 का खिताब भी दिलाया। यह टूर्नामेंट अब आयोजित नहीं होता है। आईपीएल और चैंपियंस लीग में उनकी उपलब्धियां उन्हें टी-20 क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल करती हैं। खास बात यह रही कि धौनी ने अलग-अलग दौर के खिलाड़ियों के साथ टीम को लगातार प्रतिस्पर्धी बनाए रखा। युवा खिलाड़ियों को मौका देना, अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करना और दबाव के समय संयम बनाए रखना उनकी कप्तानी की प्रमुख विशेषताएं रहीं।

धौनी की कप्तानी का सबसे बड़ा गुण मैच की परिस्थितियों को तेजी से समझना और उसी के अनुसार रणनीति बदलना रहा। वह अक्सर ऐसे फैसले लेते थे, जिनकी उम्मीद विरोधी टीम को नहीं होती थी। गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल, फील्डिंग में बदलाव और बल्लेबाजों की कमजोरी को पहचानकर योजना बनाना उनकी रणनीति का हिस्सा था। कई बार जब मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकलता दिखाई देता था, तब धौनी का शांत चेहरा और मैदान पर उनका भरोसा टीम के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता था। यही कारण रहा कि प्रशंसकों ने उन्हें 'कैप्टन कूल' का नाम दिया। उनके नेतृत्व में चेन्नई ने केवल खिताब ही नहीं जीते, बल्कि दबाव में मुकाबला करने की एक अलग पहचान भी बनाई।

दोषियों को जमानत मिलने पर बिलकिस बानो ने जताई हैरानी

नई दिल्ली। गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता बिलकिस बानो ने गहरा दुख और हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक बार फिर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही ऐसा आदेश पारित कर दिया, जिसका सीधा असर उनके जीवन और परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर पड़ता है। बिलकिस बानो के मुताबिक, उन्हें इस फैसले की जानकारी अदालत या किसी आधिकारिक माध्यम से नहीं, बल्कि मीडिया में प्रकाशित खबरों के जरिए मिली। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने का संकल्प भी जताया है।

बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से बयान जारी कर कहा कि दर्द, सदमे और अविश्वास के बीच उनके लिए अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उन्हें बुलाए बिना और उनकी बात सुने बिना आदेश पारित किया है। उनके अनुसार, किसी भी ऐसे फैसले से पहले पीड़ित की आवाज सुनी जानी चाहिए, जिसका उसके जीवन, परिवार और सुरक्षा से गहरा संबंध हो। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत ने उन्हें सूचना देने और अपना पक्ष रखने का अवसर सुनिश्चित किए बिना दोषियों की सजा निलंबित करने का आदेश कैसे दे दिया। बिलकिस बानो ने अपने बयान में वर्ष 2002 की उस भयावह घटना को याद किया, जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय वह महज 19 वर्ष की थीं। हिंसा के दौरान उनकी छोटी बच्ची, परिवार, घर और इंसानियत पर उनका भरोसा उनसे छिन गया था। एक ऐसी घटना का सामना करने के बाद, जिसका दर्द जीवनभर उनके साथ रहने वाला है,



उन्होंने न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष शुरू किया। उनके मुताबिक, बीते 24 वर्षों से वह लगातार अपने लिए ही नहीं, बल्कि देश की उन तमाम महिलाओं के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, जिन्हें हिंसा और अन्याय का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इस लंबे संघर्ष में कई बार ऐसे क्षण आए, जब उनके सामने आगे बढ़ना कठिन हो गया था। लेकिन आम लोगों, सामाजिक संगठनों और देशभर से मिले समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी। अनगिनत लोगों की एकजुटता और विश्वास से उन्हें वह साहस मिला, जिसके सहारे वह एक अदालत से दूसरी अदालत तक न्याय की गुहार लगाती रहीं। उन्होंने कहा कि जब-जब अदालतों से उन्हें न्याय मिला और उनके पक्ष में फैसला आया, तब-तब न्याय व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास फिर मजबूत हुआ। उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति आभार भी जताया, जिन्होंने इस कठिन यात्रा में उनका साथ दिया।

बिलकिस ने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने अपने जीवन को फिर से संभालने की कोशिश की। परिवार और मित्रों के सहयोग से उन्होंने उस दर्दनाक अतीत से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जीने का प्रयास किया। वह शांति चाहती थीं और धीरे-धीरे फिर से मुस्कुराना सीख रही थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने उनके भीतर पुराने भय और आशंकाओं को फिर से जगा दिया है। उन्होंने कहा कि जिस न्याय को पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, आज उसी न्याय के हाथ से निकल जाने का डर उन्हें सता रहा है। उन्हें अपने साथ-साथ अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि कहीं इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास एक बार फिर कमजोर न पड़ जाए।

बिलकिस बानो ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी है। उनके बच्चे जीवनभर उस भय और उन घावों के साये में नहीं जीने चाहिए, जिन्हें उनके परिवार ने झेला है। उन्होंने अपनी तीन वर्षीय बेटी सालेहा को याद करते हुए कहा कि वह बच्ची जीने की हकदार थी और उसकी स्मृति भी न्याय की मांग करती है। उनका कहना है कि यह लड़ाई हर उस महिला, पीड़िता और नागरिक के लिए है, जिसे अपने सम्मान, समानता और न्याय के लिए जीवनभर संघर्ष नहीं करना पड़े।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया था। दोनों दोषी इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि वे 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी ने गंभीर दिव्यांगता का हवाला भी दिया था। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने मामले में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे प्रश्नों का उल्लेख किया, जिन पर अपील की सुनवाई के दौरान विचार किया जाना आवश्यक है। इसके बाद अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए संबंधित निचली अदालत की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के अधीन जमानत देने का निर्देश दिया। उनकी अपीलों पर आगे सुनवाई होनी है।

यह आदेश ऐसे समय आया है, जब बिलकिस बानो मामला पहले भी दोषियों की समयपूर्व रिहाई को लेकर देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट देते हुए समय से पहले रिहा कर दिया था। इस निर्णय को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर सवाल उठे थे। बिलकिस बानो ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद दोषियों को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। अब दो दोषियों की सजा निलंबित होने और उन्हें जमानत मिलने से मामला फिर चर्चा में है। हालांकि, सजा निलंबित करने का आदेश दोषसिद्धि को समाप्त करने या दोषियों को बरी करने के समान नहीं है। उनकी अपीलों पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। दूसरी ओर, बिलकिस बानो ने इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उनका मुख्य सवाल यह है कि इतने संवेदनशील मामले में उनसे संवाद किए बिना और उनकी बात सुने जाने का अवसर सुनिश्चित किए बिना राहत कैसे दी गई। बिलकिस बानो की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर इस सवाल को सामने ला दिया है कि गंभीर अपराधों के मामलों में पीड़ितों की भूमिका और उनकी सुनवाई को किस तरह सुनिश्चित किया जाए।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

एआई के संकल्प

ऐसे वक्त में जब दुनिया में तकनीकी वर्चस्व वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में आ गया है, 'सैन 'फ्रांसिस्को घोषणा' के गहरे निहितार्थ और महत्व को समझना कठिन नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घोषणा पर अमेरिका और भारत सहित नौ अन्य विकसित देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर घोषणा का एक अघोषित उद्देश्य इस उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी में चीन के निरंतर बढ़ते दबदबे का मुकाबला करना भी है। चीन ने एक सुनियोजित ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापक और दीर्घकालीन निवेश किया है। इसमें दो राय नहीं कि उसकी उपलब्धियां अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाली हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने 'सैन फ्रांसिस्को घोषणा' को हकीकत बनाने को प्राथमिकता दी है। अमेरिका दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका के चलते इस दौर को 'सुपर इंटेलिजेंस युग' का नाम देता है। अमेरिका की 'पैक्स सिलिका' पहल एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करती है कि दुनिया का कोई भी देश अकेले बूते पर बेहद जटिल प्रक्रिया वाले एआई इकोसिस्टम की हर कड़ी को सुरक्षित नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर निर्माण से लेकर ऊर्जा नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक, तकनीकी प्रगति आपस में जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करती है। इस श्रृंखला में किसी भी तरह का अवरोध किसी भी देश के आर्थिक ढांचे को गहरे तक प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन नेटवर्कों में यदि किसी भी तरह का व्यवधान पैदा होता है तो उसके दूरगामी आर्थिक और भू-राजनीतिक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिये, इस सुपर इंटेलिजेंस युग वाले दौर में तमाम चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

निश्चित रूप से 'सैन फ्रांसिस्को घोषणा' पर भारत का हस्ताक्षर करना एआई के दौर में हमारी उपलब्धियों की वैश्विक स्वीकार्यता का ही परिचायक है। भारत के लिए अमेरिका और अन्य विकसित देशों के साथ शामिल होना जहां एक ओर अच्छा रणनीतिक अवसर है, वहीं देश को जिम्मेदारियों का अहसास भी कराता है। भारत हालिया वर्षों में एक उभरते हुए टेक्नोलॉजी बाजार के रूप में सामने आया है। भारत की महत्वाकांक्षा वैश्विक सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रही है। हाल के वर्षों में भारत ने आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और कई मध्यपूर्व के देशों के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारियां की हैं। जाहिर तौर पर ये विकसित व मजबूत आर्थिक देश जब कोई साझेदारी करते हैं तो उन्हें कुछ पाने की ही उम्मीद होती है। ऐसे में भारत इन मजबूत साझेदारियों, विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं, निवेश और उन्नत तकनीकों का बेहतर ढंग से लाभ उठा सकता है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि इन भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग करने से भारत पहले की तरह चंद देशों पर अत्यधिक निर्भरता कम कर सकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक देश पर निर्भर रहना आर्थिक संप्रभुता के लिये चुनौती बन सकती है। ऐसे में नये भरोसेमंद साझेदारों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिल सकती है। विडंबना यह भी है कि यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की अगुवाई करने वाली शीर्ष कंपनियों में से एक-एनवीडिया विवादों में घिरी है और उसके शेयरों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विवाहेतर संबंधों व कथित चीनी जासूस से संबंधों को लेकर इसके संस्थापक जेनसेन हुआंग को एनवीडिया से बाहर जाना पड़ा है। इस अनिश्चितता के बीच, टेक कंपनियों द्वारा एनवीडिया की चिप्स और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे भारी निवेश की निरंतरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। निस्संदेह, अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल की सफलता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, निवेश और मजबूत घरेलू क्षमताओं पर निर्भर करेगी। अंततः एआई आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ तकनीक पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है एआई के फायदे भरोसेमंद हों, सभी की पहुंच में हों और इसे व्यापक रूप से साझा किया जा सके।

वंतारा से गौ सेवा तक अनंत अंबानी की मानवीय सेवा यात्रा

> अनंत अंबानी की चर्चा केवल वंतारा तक सीमित नहीं है। हाल में उनके गौसेवा संबंधी वक्तव्य ने देश का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। एक वायरल वीडियो में उन्होंने लगभग नौ लाख गायों की देखभाल से जुड़े होने की बात कही, जिनमें करीब सात लाख गायें ऐसी बताई गईं जो दूध नहीं देतीं या आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं।

आज जब दुनिया व्यापार को प्रायः लाभ, प्रतिस्पर्धा, विस्तार और बाजार की भाषा में परिभाषित करती है, तब अनंत अंबानी का व्यक्तित्व इस स्थापित धारणा के सामने एक अलग प्रश्न खड़ा करता है-क्या बड़ी आर्थिक सफलता के साथ बड़ी मानवीय संवेदना भी संभव है? क्या अरबों-खरबों की व्यावसायिक दुनिया में करुणा, जीवदया, सेवा और पर्यावरण-संरक्षण केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के औपचारिक शब्द रहेंगे या वे जीवन-दर्शन का हिस्सा बन सकते हैं? अनंत अंबानी की गतिविधियाँ इस प्रश्न का एक सकारात्मक उत्तर देती दिखाई देती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े अनंत अंबानी आज केवल व्यापारिक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि पशु कल्याण, जीवदया और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उनकी सबसे चर्चित पहल 'वंतारा'-स्टार ऑफ द फॉरेस्ट है, जो गुजरात के जामनगर में लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्र में विकसित पशु बचाव, उपचार, पुनर्वास और संरक्षण का विशाल केंद्र है। हाल ही में केरल की 18 महीने की बीमार और घायल नन्हीं हथिनी 'माया' की जान बचाने के लिए उसे एयरलिफ्ट कराकर जामनगर स्थित अपने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वंतारा में भर्ती कराया है। रिलायंस फाउंडेशन के अनुसार वंतारा में 1.5 लाख से अधिक पशुओं और 2,000 से अधिक प्रजातियों की देखभाल की जा रही है तथा इसके लिए हजारों विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और देखभालकर्ताओं की टीम कार्यरत है।लेकिन अनंत अंबानी की चर्चा केवल वंतारा तक सीमित नहीं है। हाल में उनके गौसेवा संबंधी वक्तव्य ने देश का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। एक वायरल वीडियो में उन्होंने लगभग नौ लाख गायों की देखभाल से जुड़े होने की बात कही, जिनमें करीब सात लाख गायें ऐसी बताई गईं जो दूध नहीं देतीं या आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। उन्होंने घायल एवं संकटग्रस्त गायों



के बचाव के लिए लगभग 100 एम्बुलेंस और आठ राज्यों में सक्रिय बचाव-व्यवस्था का भी उल्लेख किया। यहीं अनंत की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। जो पशु दूध नहीं देता, जिसकी आर्थिक उपयोगिता समाप्त हो गई है, क्या उसका जीवन भी कम मूल्यवान हो जाता है? बाजार की सामान्य मानसिकता शायद इस प्रश्न का उत्तर उपयोगिता से देगी, लेकिन जीवदया की भारतीय परंपरा इसका उत्तर अस्तित्व के सम्मान से देती है।

अनंत अंबानी की गौसेवा की चर्चा इसी बिंदु पर एक व्यापक सामाजिक विमर्श को जन्म देती है-किसी जीव का मूल्य उसकी उत्पादकता से नहीं, उसके जीवन से तय होना चाहिए। यह विचार आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यापार की सफलता का अर्थ केवल अधिक उत्पादन और अधिक लाभ नहीं होना चाहिए, उसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ना चाहिए कि उस सफलता से समाज, प्रकृति और जीव-जगत को क्या मिला। यदि पूंजी संवेदना से जुड़ती है, तकनीक करुणा के साथ चलती है और उद्योग पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनता है, तो व्यापार केवल आर्थिक संस्था नहीं रहता, वह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। अनंत अंबानी की दिनचर्या से जुड़ी बातें भी इसी संवेदनशीलता की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने बताया है कि घर से निकलने से पहले वे गायों की मालिश करते हैं और उनके घर में छह गायें हैं, जिन्हें वे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराते हैं। यह बात प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। बड़े उद्योग-घराने की सुविधाओं में रहने वाला कोई युवा यदि अपने दैनिक जीवन में किसी पशु के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव को स्थान देता है, तो वह सेवा को केवल दान की गतिविधि नहीं रहने देता, उसे व्यक्तिगत संस्कार में बदल देता है।

वंतारा इस व्यक्तिगत संवेदना का संस्थागत और वैज्ञानिक विस्तार दिखाई देता है। यहां पशुओं के उपचार, पुनर्वास और संरक्षण के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ विकसित की गई हैं। रिलायंस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वंतारा में विशेषीकृत वन्यजीव अस्पताल, पशु चिकित्सा सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ, पोषण केंद्र और संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम भी संचालित हैं। यानी यह केवल 'पशुओं को बचाने' की भावना नहीं है, इसके साथ विज्ञान, चिकित्सा, जैव-विविधता और दीर्घकालीन संरक्षण को जोड़ा गया है। यही वह जगह है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति कहती है-'अहिंसा परमो धर्मः', जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है कि जैव-विविधता का संरक्षण मानव सभ्यता के भविष्य के लिए आवश्यक है। वंतारा इन दोनों विचारों को एक साझा धरातल देता है।

इसी सोच का विस्तार अक्टूबर 2026 में आरंभ हुई 'चैंपियंस ऑफ केयर' पहल में भी दिखाई देता है। विश्व पशु दिवस के अवसर पर शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत 50 से अधिक पशु कल्याण संगठनों को साथ लाने का प्रयास किया गया है, जो सामुदायिक कुत्तों, बिल्लियों, मवेशियों और अन्य पशुओं के लिए चिकित्सा, बचाव और दीर्घकालीन देखभाल का काम करते हैं। इसका लक्ष्य पशु कल्याण को केवल एक बड़े केंद्र तक सीमित रखने के बजाय देशभर के जमीनी संगठनों तक सहायता पहुँचाना है। यहाँ अनंत अंबानी के दृष्टिकोण की एक और विशेषता दिखाई देती है-केंद्रीकरण से सहयोग की ओर बढ़ना। यदि देश में पहले से काम कर रहे छोटे-छोटे पशु कल्याण संगठन संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें खत्म करने के बजाय मजबूत करना अधिक प्रभावी सामाजिक मॉडल है। यही मॉडल भविष्य में पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क का आधार बन सकता है।

अनंत की सोच को केवल भावुकता कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो इतने बड़े पशु-कल्याण अभियानों की वास्तविक कसौटी पारदर्शिता, वैज्ञानिक मानक, पशु-अधिकार, दीर्घकालीन पुनर्वास, जैव-सुरक्षा और स्वतंत्र मूल्यांकन होगी। वंतारा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रश्न और बहसें भी हुई हैं, इसलिए ऐसे विशाल संस्थानों के लिए पारदर्शिता और प्रमाण-आधारित संचालन उतना ही आवश्यक है जितना करुणा। यही आलोचनात्मक कसौटी किसी भी बड़े परोपकारी प्रयास को अधिक विश्वसनीय बनाती है। करुणा भाव है, लेकिन करुणा का स्थायी प्रभाव व्यवस्था से पैदा होता है। इसीलिए अनंत अंबानी के बारे में यह कहना अधिक उचित होगा कि वे व्यापार की पुरानी परिभाषा को अस्वीकार करने के बजाय उसमें एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि हर बड़ा व्यापार ईमानदारी और नैतिकता से ही चलता है, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनका सार्वजनिक आचरण यह संदेश देता है कि व्यावसायिक महत्वाकांक्षा और मानवीय संवेदना एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं।

अनंत अंबानी के व्यक्तित्व का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम उनके हालिया जियो संबोधन में सामने आया। 28 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ऐतिहासिक सूचीबद्धता के अवसर पर उन्होंने सफलता का श्रेय केवल परिवार या प्रबंधन को नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों को दिया। उन्होंने व्यापार को पूजा और शेयर बाजार की घंटी को मंदिर की घंटी से जोड़ते हुए कहा कि पूजा का प्रसाद बांटा जाता है और "आज जियो भारत के साथ साझा किया गया है।" उनके संबोधन के दौरान मुकेश अंबानी भावुक होकर आँसू पोंछते दिखाई दिए। यह प्रसंग महज पारिवारिक भावुकता नहीं था। इसमें व्यापार के अर्थ की एक नई व्याख्या छिपी थी-व्यापार केवल मालिक का नहीं, उससे जुड़े करोड़ों लोगों का भी होता है। जियो की सफलता को उन्होंने कर्मचारियों, तकनीशियनों, सेवा-कर्मियों, खुदरा भागीदारों और सामान्य भारतीयों की भागीदारी से जोड़ा। यही दृष्टि व्यापार को 'मैं' से 'हम' की ओर ले जाती है। एचएफसीएल के अध्यक्ष एवं दूरसंचार क्षेत्र के वरिष्ठ उद्योगपति महेंद्र नाहटा लंबे समय से जियो की यात्रा से जुड़े रहे हैं और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के निदेशक मंडल में भी रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से अनंत अंबानी की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह मानी जा सकती है कि उन्होंने तकनीक और व्यवसाय की आधुनिक दुनिया को सेवा, संस्कार और संवेदना से जोड़ने की कोशिश की है। जियो की ऐतिहासिक सफलता के अवसर पर अनंत के भावपूर्ण संबोधन में नाहटा ने भी भारतीय आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और मानवीय संवेदना के संगम की झलक देखी-ऐसा विचार उनके हालिया लेख में व्यक्त हुआ है। अनंत ने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है-क्या कारोबार का अंतिम लक्ष्य केवल लाभ है, या लाभ के साथ लोकमंगल भी? यदि व्यापार में तकनीक हो, तो वह विकास बनता है। उसमें पूंजी हो, तो वह विस्तार बनता है। लेकिन उसमें करुणा जुड़ जाए, तो वही व्यापार सेवा का माध्यम बन सकता है। अनंत अंबानी की गौसेवा, वंतारा और सामुदायिक पशु कल्याण की पहलें इसी संभावित परिवर्तन की कहानी कहती हैं।

प्रेरणा

जब संघर्ष बना ताकत, तब दुनिया ने पहचाना हुनर का दम

सफलता की चमक के पीछे अक्सर संघर्ष की ऐसी कहानी छिपी होती है, जिसे दुनिया आसानी से नहीं देख पाती। किसी के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सुविधाओं से भरा होता है, तो किसी को हर कदम पर अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कठिन परिस्थितियों में पला-बढ़ा व्यक्ति भी अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकता है। ब्रिटेन के महान फॉर्मूला वन रेसर लुईस हैमिल्टन का जीवन इसी विश्वास को साकार करता है। उन्होंने गरीबी, नस्लीय भेदभाव और संसाधनों की कमी के बीच अपने सपनों को जिंदा रखा और एक दिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मोटर रेसिंग खेल के शिखर पर पहुंच गए। लुईस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को इंग्लैंड के स्टीवनेज में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके भीतर कुछ अलग करने की इच्छा बचपन से ही मौजूद थी। महज आठ साल की उम्र में उन्होंने कार्टिंग से रेसिंग की शुरुआत की। छोटी सी रेसिंग गाड़ी पर बैठकर जब वे ट्रैक पर उतरते थे, तब उनके सामने केवल जीतने की चुनौती नहीं होती थी, बल्कि खुद को उन लोगों के बीच साबित करने का संघर्ष भी होता था, जिनके पास उनसे कहीं अधिक संसाधन और सुविधाएं थीं। कार्टिंग से लेकर फॉर्मूला वन तक का सफर बेहद खर्चीला होता है। महंगी गाड़ियां, तकनीकी उपकरण, टायर, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। लुईस के परिवार के लिए इन खर्चों को उठाना आसान नहीं था। ऐसे में उनके पिता एंथनी हैमिल्टन ने बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए उसके सपने को अपना लक्ष्य बना लिया। उन्होंने तय कर लिया कि आर्थिक परेशानियां बेटे की राह में बाधा नहीं बनेंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक मेहनत की और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बेटे के करियर को भी संभाला।

एंथनी ने बेटे के रेसिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कई नौकरियां कीं। वे आईटी मैनेजर के रूप में काम करने के अलावा अतिरिक्त काम भी करते थे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने निर्माण स्थलों पर मेहनत की और रात में बर्तन धोने जैसे काम भी किए। उनका दिन काम और जिम्मेदारियों में गुजरता था, लेकिन बेटे की प्रतियोगिता का समय आते ही वे उसके साथ खड़े दिखाई देते थे। कई बार आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती थी कि रेसिंग कार के लिए नए टायर खरीदना भी मुश्किल हो जाता था। तब वे दूसरी टीमों के इस्तेमाल किए हुए टायरों का इंतजाम करते थे। उनके लिए बेटे का सपना अपनी सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। लुईस ने अपने पिता को लगातार मेहनत करते देखा था। उनके हाथों की थकान, मेहनत के निशान और परिवार के लिए किए जा रहे त्याग ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। धीरे-धीरे रेसिंग उनके लिए केवल मनोरंजन या शौक नहीं रही, बल्कि पिता के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करेंगे, जहां उनके पिता को अपने त्याग पर गर्व महसूस हो।

रेसिंग ट्रैक पर भी उनकी राह आसान नहीं थी। उस समय मोटरस्पोर्ट में अश्वेत खिलाड़ियों की भागीदारी बहुत कम थी। कार्टिंग प्रतियोगिताओं में लुईस अक्सर अकेले अश्वेत बच्चे होते थे। उन्हें नस्लीय टिप्पणियों, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। कई बार उनकी प्रतिभा के बजाय उनके रंग को लेकर बातें की जाती थीं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता था, लेकिन लुईस ने नकारात्मक व्यवहार को अपनी प्रगति के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने हर बार अपने प्रदर्शन से जवाब देने का फैसला किया।

उनकी मेहनत और प्रतिभा ने धीरे-धीरे रेसिंग जगत का ध्यान खींचना शुरू किया। वर्ष 1998 में उन्हें मैकलारेन के ड्राइवर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह उनके करियर के लिए निर्णायक अवसर साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने जूनियर रेसिंग प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। वर्ष 2005 में फॉर्मूला श्री यूरो सीरीज और 2006 में जीपी2 चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया। इन उपलब्धियों ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मोटर रेसिंग प्रतियोगिता फॉर्मूला वन तक पहुंचा दिया। वर्ष 2007 में मैकलारेन टीम के साथ उन्होंने फॉर्मूला वन में पदार्पण किया। पहले ही सीजन में उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली रहा कि वे विश्व चैंपियनशिप जीतने के करीब पहुंच गए। हालांकि खिताब उनसे दूर रह गया, लेकिन उन्होंने अगले ही वर्ष इतिहास रच दिया। 2008 में ब्राजील ग्रां प्री के अंतिम मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपना पहला विश्व खिताब हासिल किया। महज 23 वर्ष की उम्र में वे फॉर्मूला वन इतिहास के पहले अश्वेत विश्व चैंपियन बने। यह जीत उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जो सीमित अवसरों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। इसके बाद उनकी उपलब्धियों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। वर्ष 2013 में मर्सिडीज टीम से जुड़ने के बाद उनके करियर ने नई ऊंचाइयां छुईं। उन्होंने 2014 और 2015 के बाद 2017, 2018, 2019 और 2020 में भी विश्व चैंपियनशिप जीती। इस प्रकार वे सात बार के विश्व चैंपियन बने और महान रेसर माइकल शूमाकर के सर्वाधिक सात खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की। रेस जीत और पोल पोजीशन के मामले में भी उन्होंने फॉर्मूला वन में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए। हैमिल्टन ने अपनी पहचान को केवल रेसिंग तक सीमित नहीं रखा। वे नस्लीय समानता, सामाजिक न्याय और खेलों में विविधता को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन उसकी मेहनत और प्रतिभा से होना चाहिए, न कि उसकी त्वचा के रंग या पारिवारिक पृष्ठभूमि से। लुईस हैमिल्टन की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सपनों की ऊंचाई आर्थिक स्थिति से तय नहीं होती। एक पिता का अथक परिश्रम और एक बेटे का अटूट संकल्प मिलकर ऐसी कहानी लिख सकते हैं, जो पीढ़ियों को प्रेरित करे। कभी पुराने टायरों के सहारे रेसिंग करने वाला बच्चा जब सात बार विश्व चैंपियन बना, तो उसने साबित कर दिया कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज महंगे साधन नहीं, बल्कि कठिनाइयों से लड़ने का साहस है।

साफ हवा मिले तो सालाना बचे 90 लाख से भी अधिक जिंदगियां

बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य लगती है पर यदि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन की ही माने तो केवल शुद्ध हवा मिलने लगे तो साल भर में देश-दुनिया में 90 लाख से अधिक जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण से अत्यधिक चिंताग्रस्त है। इसका कारण भी है और वह यह कि आज प्रकृति की विकृति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान, जंगलों में दावानल, समुद्र में आए दिन तूफान, सुनामी और भू स्खलन से लेकर भूकंप की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेसियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है तो समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी तो दूर आए दिन वायु गुणवत्ता में कमी, धुंध और कोहरा आम है तो दुनिया के बड़े शहरों में ग्रेप पाबंदिया तक लगाने को बाध्य होना पड़ रहा है। जनजीवन ही नहीं स्वास्थ्य तक प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर जब दिसंबर 2015 में पेरिस में दुनिया के देषों की कोप 21 के दौरान ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधी की रुपरेखा तय हुई और 4 नवंबर, 2016 को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते पर क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाये तो समूची दुनिया में आशा का संचार हुआ है। आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओजोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं तो दूसरी और यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमेरिका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया है। हांलाकि यह अमेरिका का गैर जिम्मेदारान कदम है और दुनिया के देषों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है। पर इससे अधिक और खासतौर से 300 से अधिक एक्यूआई अत्यधिक खतरनाक स्थिति माना गया है। आज हवा के जहरीली होने के कारण सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों को दो चार होना पड़ता है। प्रदूषित हवा के चलते फेफडें, हृदय, स्ट्रोक और डिमेंशिया की बीमारी का विस्तार हो रहा है। अरबों रुपए इन बीमारियों के ईलाज में खर्च हो रहे हैं तो लाखों जाने प्रतिवर्ष इनके कारण जा रही है। यदि भारत की ही बात करें तो स्वास्थ्यकर मानकों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त सांस लेने के हवा नहीं मिलने के कारण सालाना 6 से 8 लाख लोग फेफड़ो की बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक ह्रदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्ट्रोक से प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है और करीब 5 से 6 लाख लोग स्ट्रोक के अटेक से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक कि ढ़ाई से तीन लाख लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। यह हालात अपने आपमें चिंताजनक है। दुनियाभर की मानें तो एक करोड़ से भी अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण जनित रोगों से काल के मुंह में समा जाते हैं। केवल दवा आदि में ही अरबों डालर रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके 2.5 पीएम स्तर पर लाने के ठोस प्रयास किये जाएं तो अरबों डॉलर ही नहीं अपितु लाखों जिंदगानी को बचाया जा सकता है। साफ हवा होगी तो जान लेवा बीमारियों से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और देखभाल में होने वाले खर्चे को इकोनोमी को बूस्ट करने में काम में लिया जा सकेगा। अरबों रुपयों की बचत होगी तो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा।

दरअसल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जैविक उर्जा साधन है। कारखानों व ईंधन के रुप में उपयोग होने वाली जैविक इंर्धन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित कर रहा है। हांलाकि पराली, पटाखों और अन्य कारकों भी कारण माना जा रहा है। पॉवर सेक्टर, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक घटनाओं व अन्य कारणों के साथ ही परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में उपयोग होने वाला डीजल-पेट्रोल और निर्माण कार्यों और कचरा अपशिष्ट से वायु प्रदूषण फैल रहा है। हांलाकि रिन्यूवल एनर्जी और ई व्हीकल के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है पर अभी भी पॉवर सेक्टर, परिवहन वाहनो आदि में जैविक ईंधन की निर्भरता बहुत अधिक और चिंतनीय स्तर पर है। समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है और इस दिषा में दुनिया के देशों को तेजी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह अध्ययन केवल कुछ देशों या क्षेत्रों तक सीमित ना होकर दुनिया के 136 देशों के अध्ययन का परिणाम है और इसके नतीजे ना केवल दुनिया को चेताने वाले हैं अपितु समय रहते ठोस प्रयास करने की साफ साफ चेतावनी भी है।

अभियान

तुलसी चालीसा का पाठ खोलेगा सौभाग्य के द्वार, नवग्रह शांति और सुख-समृद्धि की है धार्मिक मान्यता

भारतीय सनातन संस्कृति में तुलसी का स्थान अत्यंत पवित्र और विशिष्ट माना गया है। घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवार की सुख-शांति, संस्कार और आध्यात्मिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है और उनकी नियमित पूजा को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी माता की आराधना करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी धार्मिक विश्वास के चलते अनेक घरों में सुबह-शाम तुलसी के सामने दीपक जलाने, जल अर्पित करने और उनकी परिक्रमा करने की परंपरा निभाई जाती है। तुलसी चालीसा का नियमित पाठ भी इसी उपासना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, पारिवारिक कलह कम होती है और सुख-समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं।

पौराणिक मान्यताओं में तुलसी माता की उत्पत्ति और महिमा का संबंध देवी वृंदा की कथा से जोड़ा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वृंदा को भगवान विष्णु की अनन्य भक्त बताया गया है। उनकी भक्ति, तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पूजनीय होने का वरदान दिया। इसी कारण तुलसी को भगवान हरि की अत्यंत प्रिय माना जाता है। उन्हें हरिप्रिया नाम से भी संबोधित किया जाता है। धार्मिक परंपरा में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा के दौरान तुलसी दल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। यहां तक कि भगवान को भोग लगाते समय भी तुलसी दल रखने की परंपरा है। माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा और भोग पूर्ण नहीं होते।

तुलसी चालीसा में माता तुलसी की महिमा और उनकी कृपा का गुणगान किया गया है। इसके पाठ के माध्यम से भक्त माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। धार्मिक विश्वास है कि प्रतिदिन तुलसी चालीसा पढ़ने से घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है। व्यक्ति के मन में भक्ति और सद्भाव की भावना मजबूत होती है। नियमित पाठ से जीवन में अनुशासन आता है और सुबह का समय पूजा-पाठ में लगाने से दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ होती है। जो लोग मानसिक तनाव, चिंता और पारिवारिक परेशानियों से घिरे रहते हैं, उनके लिए भी नियमित प्रार्थना और ध्यान मन को शांति देने वाला अभ्यास हो सकता है।

धार्मिक मान

छत पर बंदर के हमले से घबराई महिला, साइलेंट अटैक से मौत

कोटा। राजस्थान के कोटा में बंदरों के हमले से घबराई एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। घर की छत पर कपड़े सुखाने गई 28 वर्षीय महिला पर अचानक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। इसी दौरान एक बंदर महिला के कंधे पर चढ़ गया और उसके चेहरे तथा पीठ पर पंजे मारने लगा। अचानक हुए इस हमले से महिला बुरी तरह घबरा गई और कुछ ही देर में छत पर अचेत होकर गिर पड़ी। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक, डॉक्टरों ने महिला की मौत का कारण साइलेंट अटैक बताया है। इस घटना से परिवार में मातम पसरा है। मृतका की छह साल की बेटी है, जिसके सिर से मां का साया उठ गया।

यह घटना रविवार दोपहर कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके में स्थित जागाओं के मोहल्ले की है। यहां रहने वाली रेनू भट्ट पत्नी प्रदीप भट्ट रोजमर्रा के काम के सिलसिले में घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी, जो पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल देगी। रेनू छत पर कपड़े सुखा रही थीं, तभी अचानक वहां बंदरों का एक झुंड पहुंच गया। बंदरों को देखकर उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन झुंड में शामिल एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया।



प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, बंदर अचानक महिला के ऊपर कूद पड़ा और उनके कंधों पर चढ़कर बैठ गया। रेनू ने उससे बचने के लिए पास में पड़ी लकड़ी उठाई, लेकिन बंदर पीछे हटने के बजाय और आक्रामक हो गया। उसने महिला के चेहरे और पीठ पर पंजे मारने शुरू कर दिए। अचानक हुए इस हमले से रेनू घबरा गईं। बंदर को हटाने की कोशिश के बीच उनकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य छत की ओर दौड़े, लेकिन तब तक रेनू जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थीं। उनके चेहरे और पीठ पर बंदर के नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे।

रेनू के जेठ अर्जुन भट्ट ने बताया कि महिला की चीख सुनकर परिवार के लोग तुरंत छत पर पहुंचे। वहां रेनू जमीन पर गिरी हुई थीं और बंदर अभी आसपास मौजूद थे। परिजनों ने किसी तरह बंदरों को भगाया और रेनू को संभालकर अस्पताल पहुंचाया। परिवार को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिलने से उनकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जेठ के मुताबिक, डॉक्टरों ने जांच के बाद साइलेंट अटैक आने की बात कही। अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि रोजमर्रा के सामान्य काम के दौरान रेनू के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया।

परिजनों के अनुसार, रेनू की उम्र महज 28 वर्ष थी और उनकी छह साल की बेटी है। मां की अचानक मौत से बच्ची के जीवन में बड़ा खालीपन आ गया है। परिवार में इस घटना के बाद से शोक का माहौल है। मोहल्ले के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बंदरों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। बंदरों के झुंड अक्सर घरों की छतों और गलियों में पहुंच जाते हैं। कई बार लोग उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर आक्रामक होकर हमला करने लगते हैं। लोगों को डर रहता है कि कहीं किसी दिन किसी बच्चे, बुजुर्ग या महिला के साथ कोई गंभीर हादसा न हो जाए।

घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस पार्षद विनोद कुमार भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इलाके में बंदरों की समस्या को गंभीर बताया। पार्षद के अनुसार, स्थानीय स्तर पर बंदरों की समस्या को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और क्षेत्र से बंदरों को पकड़ने की मांग की जाएगी। उनका कहना है कि जब तक बंदरों की बढ़ती संख्या और उनके आक्रामक व्यवहार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहेगा। वहीं, नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर मोतीलाल ने बताया कि शहर के जिन इलाकों से बंदरों की समस्या को लेकर शिकायतें मिलती हैं, वहां पिंजरे लगवाकर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि कंसुआ इलाके में भी पहले पिंजरे लगवाए गए थे, लेकिन बंदर उनमें कैद नहीं हुए। अब इस क्षेत्र में दोबारा पिंजरे लगवाए जाएंगे, ताकि बंदरों को पकड़कर आबादी वाले इलाकों से हटाया जा सके। नगर निगम की ओर से यह भी कहा गया है कि शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्रों में कार्रवाई की जाती है। कोटा नगर निगम के कमिश्नर ओपी मेहरा के मुताबिक, इस साल शहर के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत एक जनवरी से अब तक कुल 1,562 बंदरों को पकड़ा जा चुका है। इसके बावजूद कई मोहल्लों में बंदरों की समस्या बनी हुई है। कंसुआ और आसपास के इलाकों में दोबारा पिंजरे लगाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर शहरी इलाकों में बंदरों के बढ़ते आतंक और नागरिक सुरक्षा की समस्या को सामने ला दिया है। घरों की छतों, गलियों और बाजारों में बंदरों के झुंड का पहुंचना अब कई शहरों में आम समस्या बनती जा रही है। लोग अक्सर अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों के लिए बंदरों का आक्रामक व्यवहार गंभीर खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बंदरों को छेड़ना, उनके करीब जाना या उन्हें हाथ से खाना खिलाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में स्थानीय निकायों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ बंदरों के प्रबंधन के लिए प्रभावी और स्थायी व्यवस्था करनी होगी।

रेनू भट्ट की मौत का मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस समस्या की ओर भी ध्यान दिलाता है, जिससे शहर के कई मोहल्लों के लोग जूझ रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों ने मौत का कारण साइलेंट अटैक बताया है और बंदर के हमले तथा मौत के बीच चिकित्सकीय संबंध की पुष्टि अलग से नहीं हुई है, लेकिन घटना के दौरान हुई घबराहट और उसके बाद महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि नगर निगम इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंसुआ और आसपास के इलाकों में बंदरों को पकड़ने की ठोस कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी पीड़ा का सामना न करना पड़े।

भावनगर मंडल में रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए RPF की सतर्कता एवं तत्परता से तीन मामलों में प्रभावी कार्रवाई

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के समन्वय से निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026 के दौरान चलाला, राणपुर एवं लीलिया में ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारियों के साथ मारपीट की तीन घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 11 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें 5 विधि संघर्षरत बालक शामिल हैं।

इनमें 30 जुलाई को चलाला रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट श्री तेजराज मीणा के साथ मारपीट के मामले में 7 आरोपियों, 10 अगस्त को राणपुर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर श्री अनिल कुमार तिवारी के साथ मारपीट के मामले में 2 आरोपियों तथा 9 अक्टूबर को लीलिया रेलवे फाटक संख्या 41/SPL पर गेटमैन श्री मंसाराम कांशीराम दहीवाले के साथ मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा गया। सभी मामलों में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर, श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। RPF एवं GRP के समन्वित प्रयासों से इन मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश वर्मा ने RPF एवं GRP के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता एवं तत्परता की सराहना की। मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, श्री अजय शर्मा के मार्गदर्शन में RPF द्वारा यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों की सुरक्षा तथा अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

रेलवे प्रशासन सभी यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों से रेलवे परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल RPF या रेलवे प्रशासन को देने की अपील करता है।

ऑपरेशन अमानत के तहत RPF ने महिला यात्री का 17,000 मूल्य का खोया हुआ मोबाइल सुरक्षित लौटाया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को सुरक्षित वापस लौटाने के लिए 'ऑपरेशन अमानत' के तहत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 16 नवंबर 2026 को जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर RPF की सतर्कता एवं तत्परता से एक महिला यात्री का खोया हुआ मोबाइल फोन सुरक्षित बरामद कर उसे सही-सलामत वापस सौंपा गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर, श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 16 नवंबर को दोपहर लगभग 15:10 बजे जूनागढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 01 पर RPF कार्यालय के सामने स्थित बेंच पर एक मोबाइल फोन लावारिस अवस्था में मिला। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल श्री राजेश चौहान ने आसपास मौजूद यात्रियों से मोबाइल के संबंध में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस पर अपना दावा नहीं किया।



इसके बाद मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए RPF पोस्ट पर लाया गया।

कुछ समय पश्चात जूनागढ़ निवासी महिला यात्री किंजल बेन, पुत्री श्री जीनाभाई वाजा, RPF पोस्ट पर पहुंचीं और बताया कि जूनागढ़ से वेरावल की यात्रा के दौरान उनका मोटोरोला G-54 मोबाइल फोन, जिसकी अनुमानित कीमत 17,000 है, प्लेटफॉर्म पर छूट गया है। उन्होंने अपना सामान्य टिकट प्रस्तुत किया। RPF कर्मियों द्वारा मोबाइल दिखाए जाने पर महिला यात्री ने उसकी पहचान की। आवश्यक जांच एवं पुष्टि के बाद मोबाइल फोन उन्हें सही-सलामत सुपुर्द कर दिया गया।

अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर महिला यात्री ने रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता, ईमानदारी एवं त्वरित सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश वर्मा ने RPF कर्मियों की सतर्कता एवं तत्परता की सराहना करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके सामान की देखभाल रेलवे की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। 'ऑपरेशन अमानत' के माध्यम से यात्रियों को उनके खोए हुए सामान वापस दिलाने के लिए RPF द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

मंडल सुरक्षा आयुक्त, भावनगर, श्री अजय शर्मा के मार्गदर्शन में भावनगर मंडल का रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यात्रियों को बेहतर सेवा एवं सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं के लिए जीसीआरआई की नई पहल : महिलाओं के नियमित एचआईवी उपचार में एचपीवी डीएनए-आधारित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को भी शामिल किया गया

एचआईवी के साथ जीवन जी रही महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा, अब तक 1542 एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं की एचपीवी डीएनए टेस्टिंग के जरिए स्क्रीनिंग की गई

गांधीनगर : अहमदाबाद स्थित गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआई) ने एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। जिसके अंतर्गत इन महिलाओं के नियमित एचआईवी उपचार के हिस्से के तौर पर एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) डीएनए-आधारित सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) की स्क्रीनिंग को भी शामिल किया गया है। यह पहल अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में स्थित एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर के माध्यम से लागू की जा रही है। इस पहल को 'एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर एंड सर्विस डिलीवरी' की श्रेणी में फिक्की हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से भी सम्मानित किया गया है। एचआईवी के साथ जीवन जी रही महिलाओं में हाई-रिस्क ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) का इंफेक्शन लंबे समय तक बने रहने और इसके कारण सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। नियमित एचआईवी उपचार के साथ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को जोड़ने से इस संवेदनशील वर्ग की महिलाओं में रोग की जल्दी पहचान और समय पर उपचार करने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार लाने का अवसर भी मिलता है।



उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ ही निवारक स्वास्थ्य देखभाल और रोगों का जल्दी पता लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार भी राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रफुल पानसेरिया के मार्गदर्शन में राज्य का स्वास्थ्य विभाग कैंसर सहित गंभीर रोगों का शीघ्र निदान करने और संवेदनशील वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गुजरात सरकार और गुजरात कैंसर सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआई) राज्य में कैंसर के उपचार और देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर में उभरा है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस यह संस्था कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए समर्पित है। साथ ही, संस्था अपनी इस नई पहल के जरिए एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

जीसीआरआई की पहल : मुख्य उपलब्धियां एवं नतीजे

जीसीआरआई ने मार्च 2025 में यह पहल लागू की थी। इस पहल के अंतर्गत अब तक मिली उपलब्धियां और नतीजे निम्नानुसार हैं :

- एचआईवी के साथ जीवन जी रहीं 1542 महिलाओं की एपीवी डीएनए टेस्टिंग के जरिए स्क्रीनिंग की गई।
- 319 महिलाओं (20.69 फीसदी) का एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जबकि 1223 महिलाओं का टेस्ट नेगेटिव आया।
- स्क्रीनिंग के बाद आगे की जांच और मूल्यांकन के लिए 150 महिलाओं की कोल्पोस्कोपी की गई।
- प्रीकैंसरस सर्वाइकल लीजन (सीआईएन) यानी गर्भाशय ग्रीवा पर कैंसर से पहले की अवस्था वाले 94 मामले सामने आए, जिनमें सीआईएन 1 के 63 मामले, सीआईएन 2 के 30 और सीआईएन 3 का 1 मामला शामिल है।
- सर्वाइकल कैंसर का प्रारंभिक चरण का भी 1 मामला सामने आया, जिससे समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप और उपचार संभव हो सका। महिलाओं के इस समूह में एचपीवी पॉजिटिविटी की दर 20.69 फीसदी दर्ज की गई, जो गुजरात की शहरी सामान्य आबादी में दर्ज 4.82 फीसदी और ग्रामीण सामान्य आबादी में दर्ज 5.22 फीसदी से बहुत अधिक है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहीं महिलाओं के लिए ऐसी लक्षित स्क्रीनिंग कितनी महत्वपूर्ण है।
- जीसीआरआई की पहल को मिला फिक्की हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026
- इस पहल को 'इन पेशेंट केयर एंड सर्विस डिलीवरी' (मरीज की देखभाल और सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) की श्रेणी में 'फिक्की हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026' से सम्मानित किया गया है। यह अवॉर्ड नियमित
- एचआईवी उपचार के साथ कैंसर की रोकथाम और जल्दी निदान को जोड़कर रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल को अधिक मजबूत करने के जीसीआरआई के प्रयासों की सराहना करता है।

गुजरात के दूसरे एआरटी केंद्रों में भी इस पहल का विस्तार होगा

जीसीआरआई इस एकीकृत मॉडल को अधिक मजबूत बनाने के साथ ही इसकी व्यावहारिक संभावनाओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर गुजरात के दूसरे एआरटी केंद्रों में भी इसका विस्तार करने की दिशा में प्रयास करेगा। इस दृष्टिकोण से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तक पहुंच बढ़ेगी, इसके निदान में होने वाली देरी कम होगी तथा एचआईवी के साथ जीवन जी रही महिलाओं के लिए कैंसर की समान देखभाल सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

यह पहल गुजरात सरकार और जीसीआरआई की निवारक स्वास्थ्य देखभाल, कैंसर के शीघ्र निदान और संवेदनशील वर्गों के स्वास्थ्य संबंधी नतीजों में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

सर्दियों में भी त्वचा की चमक रहे बरकरार अपनाएं प्राकृतिक देखभाल के ये आसान उपाय

सर्दियों की दस्तक के साथ ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। हल्की ठंड को हमारा शरीर आसानी से सहन कर लेता है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का असर त्वचा पर साफ दिखाई देने लगता है। इस मौसम में ठंडी हवाओं और वातावरण में नमी की कमी के कारण त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है। नतीजतन त्वचा रूखी, बेजान और खुरदरी हो जाती है। कई बार त्वचा पर खुजली, लालिमा और दरारें भी पड़ने लगती हैं। इसका सबसे अधिक असर गालों, होंठों और हाथों पर दिखाई देता है। इसलिए सर्दियों में त्वचा की खूबसूरती और कोमलता बनाए रखने के लिए सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी अतिरिक्त देखभाल जरूरी हो जाती है।

सर्दियों में त्वचा की देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी प्राकृतिक नमी को बनाए रखना है। ठंडी हवा त्वचा की ऊपरी परत से नमी कम कर देती है। यदि त्वचा को समय पर मॉइस्चराइज न किया जाए, तो उसका प्राकृतिक सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में त्वचा पर रूखापन बढ़ता है और चेहरे की चमक कम होने लगती है। सर्दियों की शुरुआत से ही नियमित देखभाल की आदत अपना ली जाए, तो कड़ाके की ठंड में भी त्वचा को काफी हद तक स्वस्थ और मुलायम रखा जा सकता है।

इस मौसम में गालों की त्वचा विशेष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि चेहरे का यह हिस्सा ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क में रहता है। कई बार गाल लाल दिखाई देने लगते हैं। ठंड के प्रभाव से त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाओं में बदलाव आता है। तापमान में गिरावट के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और गर्माहट बनाए रखने के लिए रक्त प्रवाह में बदलाव होता है। ठंड से प्रभावित त्वचा में जलन और लालिमा भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा त्वचा में नमी और पोषण की कमी होने पर गालों का रूखापन और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऐसे में चेहरे को ठंडी हवा से बचाना और नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। बाहर निकलते समय स्कार्फ या मुलायम कपड़े से चेहरे को ढकना भी उपयोगी हो सकता है।

त्वचा की खूबसूरती केवल बाहरी देखभाल से नहीं आती, बल्कि शरीर को भीतर से पर्याप्त पोषण देना भी जरूरी है। सर्दियों में अक्सर लोग प्यास कम महसूस करते हैं और पानी पीने की मात्रा घटा देते हैं। इसका असर शरीर और त्वचा दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें। सामान्य तौर पर आठ से दस गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, हालांकि इसकी जरूरत व्यक्ति की उम्र, गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। यदि ठंड के कारण सादा पानी पीने का मन न करे, तो गुनगुना पानी, नारियल पानी और हरी सब्जियों का सूप भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। त्वचा की प्राकृतिक बनावट और लचीलापन बनाए रखने में कोलेजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर में कोलेजन के निर्माण में मदद करने के लिए विटामिन-सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन लाभकारी है। संतरा, नींबू, मौसंबी और अंगूर जैसे खट्टे फल, टमाटर तथा शिमला मिर्च को भोजन में शामिल करें। इसके साथ पालक, पत्तागोभी, शलजम जैसी सब्जियां भी खाएं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, अलसी के बीज और चिया सीड्स जैसे नट्स और बीज त्वचा को आवश्यक पोषक तत्व और स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार त्वचा को भीतर से स्वस्थ रखने में मदद करता है।

सर्दियों में होंठों की देखभाल भी बेहद जरूरी है। ठंडी हवा और कम नमी के कारण होंठों की ऊपरी परत जल्दी सूखने लगती है। होंठों की त्वचा चेहरे के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक नाजुक होती है और उसमें प्राकृतिक तेल बनाने वाली ग्रंथियां नहीं होतीं। इसलिए मौसम में बदलाव का असर उन पर सबसे पहले दिखाई देता है। होंठ सूखने, फटने और उनमें दरारें पड़ने की समस्या आम हो जाती है। फटे होंठ न केवल दर्द और जलन पैदा करते हैं, बल्कि चेहरे की सुंदरता को भी प्रभावित करते हैं। सर्दियों में कई लोग चाय और कॉफी का सेवन बढ़ा देते हैं। यदि इन पेय पदार्थों के कारण पानी पीना कम हो जाए, तो शरीर में पानी की कमी का असर होंठों पर भी दिखाई दे सकता है। घर के अंदर हीटर या ब्लोअर की गर्म और शुष्क हवा भी होंठों की नमी कम कर देती है। ऐसे में होंठों को बार-बार जीभ से गीला करने की आदत से बचना चाहिए। लार सूखने के बाद होंठों को और अधिक रूखा बना सकती है। दिन में कई बार अच्छा लिप बाम या पेट्रोलियम जेली लगाएं। नारियल तेल जैसे कोमल मॉइस्चराइजर भी होंठों को मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। रात को सोने से पहले होंठों पर पेट्रोलियम जेली की एक परत लगाना उपयोगी है। यदि ग्लिसरीन या गुलाब जल का इस्तेमाल करना चाहें, तो ऐसे उत्पाद चुनें जो होंठों के लिए सुरक्षित हों और उनसे जलन न होती हो। होंठों पर लगातार कालापन, सूजन या घाव बने रहने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

अहमदाबाद मंडल में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन



पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में समारोह आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धापूर्वक किया गया। इस अवसर पर अहमदाबाद मंडल के समस्त शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी जीवन, उनके अदम्य साहस, संघर्ष, त्याग एवं बलिदान तथा जनजातीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष, सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान तथा जनजातीय अस्मिता के संरक्षण का अनुपम उदाहरण है। धरती आबा के नाम से विख्यात भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवनकाल में जनजातीय समाज को संगठित कर उनके अधिकारों एवं स्वाभिमान के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया।

मंडल रेल प्रबंधक ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों, उनके संघर्षशील व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं समाज के उत्थान की भावना से प्रेरणा ग्रहण करें तथा उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को अपने जीवन एवं कार्यव्यवहार में आत्मसात करें। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के प्रति सम्मान एवं जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम का समापन भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों, उनके त्याग एवं बलिदान तथा जनजातीय समाज और राष्ट्र के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए किया गया।

आर्थिक तंगी से बंद हुई अखबारी वेबसाइटों को फिर मिलेगा डिजिटल जीवन! HPCMF की निःशुल्क ई-पेपर वेबसाइट और तकनीकी सहयोग की पहल

नई दिल्ली। डिजिटल पत्रकारिता के विस्तार के बीच छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। वर्षों से प्रिंट माध्यम में पाठकों तक अपनी बात पहुँचाने वाले अनेक प्रकाशनों के लिए वेबसाइट बनाना और उसे लगातार संचालित रखना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है। होस्टिंग, तकनीकी रखरखाव, सुरक्षा, प्रीमियम थीम और आवश्यक सॉफ्टवेयर का खर्च कई बार उनकी क्षमता से बाहर हो जाता है। नतीजतन, कुछ समाचार-पत्र अपनी वेबसाइट बंद करने को मजबूर होते हैं, जबकि कई प्रकाशन चाहकर भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। इसी समस्या को देखते हुए हरिश्चंद्र प्रेस क्लब एंड मीडिया फाउंडेशन (HPCMF) ने देश के पंजीकृत समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को निःशुल्क डिजिटल ई-पेपर वेबसाइट तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की पहल की घोषणा की है।

संस्था के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण बंद हो चुकी समाचार-पत्रों की वेबसाइटों को दोबारा शुरू करने के साथ उन प्रिंट प्रकाशनों को डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है, जिनके पास वेबसाइट निर्माण और संचालन के लिए पर्याप्त आर्थिक या तकनीकी संसाधन नहीं हैं। प्रथम चरण में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRGI), पूर्व में RNI, के अंतर्गत पंजीकृत समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को शामिल किया जाएगा। यह पहल केवल वेब होस्टिंग उपलब्ध कराने तक सीमित रखने के बजाय एक संपूर्ण तैयार वेबसाइट और उससे जुड़ी तकनीकी सुविधाएँ देने पर केंद्रित है। HPCMF के प्रस्ताव के अनुसार, इसमें वेबसाइट निर्माण और प्रारंभिक सेटअप, डिजाइन एवं थीम, आवश्यक प्लगइन और सॉफ्टवेयर का कॉन्फिगरेशन, होस्टिंग, SSL, सुरक्षा और बैकअप जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। जिन प्रकाशनों की वेबसाइट पहले से मौजूद थी, उनके उपलब्ध डेटा और सामग्री को नई होस्टिंग पर स्थानांतरित करने में भी तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। वेबसाइट शुरू होने के बाद आवश्यक बदलावों, तकनीकी समस्याओं और रखरखाव के लिए भविष्य में भी निःशुल्क सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है।

इस पहल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल उपस्थिति अब केवल बड़े मीडिया संस्थानों की जरूरत नहीं रह गई है। जिला, तहसील और छोटे शहरों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र भी अपने नियमित पाठकों के साथ नई पीढ़ी तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए वेबसाइट का खर्च केवल शुरुआत तक सीमित नहीं होता। डोमेन, होस्टिंग, सुरक्षा और तकनीकी रखरखाव पर लगातार होने वाला व्यय छोटे प्रकाशनों के सीमित बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। कई बार डिजिटल मंच से होने वाली आय उसकी संचालन लागत की भरपाई भी नहीं कर पाती। ऐसे में तकनीकी संसाधनों का साझा सहयोग छोटे प्रकाशनों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है।

HPCMF की इस पहल के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रकाशनों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला, वे समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ जिनकी वेबसाइट आर्थिक कारणों से बंद हो चुकी है और जिन्हें फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता चाहिए। दूसरा, वे प्रकाशन जिनकी वेबसाइट अभी चल रही है, लेकिन होस्टिंग और रखरखाव का खर्च उठाना कठिन हो रहा है। तीसरा, वे पंजीकृत प्रिंट प्रकाशन जिन्होंने अब तक आर्थिक या तकनीकी कारणों से अपनी वेबसाइट शुरू नहीं

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से पंचमहाल के हालोल तहसील के नूरपुरा में ऊर्जा क्षेत्र की अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं से युक्त नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास संपन्न हुआ

गांधीनगर : पंचमहाल जिले के आदिवासी क्षेत्र में ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति का आरंभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से मंगलवार को टीएमसी ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा पंचमहाल में स्थापित किए जाने वाले अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं से युक्त नए प्लांट का शिलान्यास संपन्न हुआ।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में टीएमसी की यह परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात आज रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। दो दशक पहले इसी जिले के चांपानेर से शुरू हुई 'ज्योतिग्राम योजना' ने देश के बिजली उत्पादन और वितरण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। अब टीएमसी का यह नया प्लांट वार्षिक 78,000 एमवीए उत्पादन क्षमता के साथ निर्मित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्लांट न केवल ऊर्जा सुरक्षा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर भी उत्पन्न करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वडोदरा, सावली, हालोल और कालोल का संपूर्ण क्षेत्र हाईटेक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है । उन्होंने जोड़ा कि इस उद्योग के आगमन से एमएसएमई, छोटे सप्लायर्स और सहायक उद्योगों को नई शक्ति मिलेगी, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपेक्षा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री के विकास के 'सप्तधारा' विजन के अंतर्गत आने वाले वर्षों में टीएमसी की यह नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के विकास, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। टीएमसी ट्रांसफॉर्मर्स के एम.डी. श्री एच. एन. शुक्ला ने स्वागत भाषण में संपूर्ण कार्यक्रम के साथ-साथ कंपनी का परिचय प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को टीएमसी कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि का चेक कन्या केळवणी निधि में अर्पित किया।

इस अवसर पर छोटा उदेपुर के सांसद श्री जसुभाई राठवा, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नीरज पटेल, मांजलपुर के विधायक श्री सतीश पटेल, जिला अग्रणी श्री मयंक देसाई, हालोल तहसील पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीरूबेन बारीया, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, जिला विकास अधिकारी श्री प्रणव विजयवर्गीय, सहायक कलेक्टर श्री स्मित पंचाल तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

एआई के दौर में बदल जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की भूमिका

नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने सॉफ्टवेयर उद्योग के कामकाज और पेशेवर भूमिकाओं में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का बड़ा हिस्सा कोड लिखने, प्रोग्राम तैयार करने और तकनीकी समस्याओं का समाधान विकसित करने में लगाता था, लेकिन आने वाले समय में उनकी जिम्मेदारी का स्वरूप बदल सकता है। इन्फोसिस के सह-संस्थापक एस. गोपालकृष्णन का कहना है कि एआई के विस्तार के साथ इंजीनियरों को केवल कोड लिखने तक सीमित रहने के बजाय एआई से तैयार किए गए कोड की समीक्षा, जांच और प्रमाणन करने में दक्ष होना होगा। इसके लिए तकनीकी पेशेवरों को नए कौशल और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई से कोड तैयार होने के बावजूद उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मानव विशेषज्ञों की ही रहेगी। बेंगलुरु टेक समिट 2026 में अपने विचार रखते हुए गोपालकृष्णन ने कहा कि कोडिंग उन शुरुआती क्षेत्रों में शामिल है, जहां एआई ने काम को स्वचालित करना शुरू कर दिया है। अब एआई आधारित उपकरण कुछ ही समय में ऐसे प्रोग्राम और कोड तैयार कर सकते हैं, जिन्हें लिखने में पहले इंजीनियरों को काफी समय लगाना पड़ता था। इससे सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया तेज हो रही है और कंपनियों के लिए कम समय में नए उत्पाद तैयार करना संभव बन रहा है। हालांकि, उनका मानना है कि इस बदलाव को मानव इंजीनियरों की जरूरत समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि इससे इंजीनियरों के काम का स्वरूप बदलेगा और उनकी विशेषज्ञता की जरूरत नए क्षेत्रों में बढ़ेगी। गोपालकृष्णन के अनुसार, एआई से तैयार होने वाला कोड हमेशा सही और भरोसेमंद हो, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। कई बार एआई ऐसे निर्देशों को भी सही मानकर परिणाम दे सकता है, जिनमें तकनीकी गलती या अस्पष्टता मौजूद हो। कभी-कभी कोड में ऐसी खामियां रह सकती हैं, जो सामान्य परीक्षण में तुरंत पकड़ में नहीं आतीं। यदि इन गलतियों को बिना जांचे किसी सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रणाली में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए एआई द्वारा तैयार किए गए कोड को अंतिम रूप देने से पहले उसकी तकनीकी जांच और गुणवत्ता परीक्षण आवश्यक होगा।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एआई कभी-कभी भ्रमित होकर गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर कोड तैयार कर सकता है। इससे प्रोग्राम में ऐसी खामियां रह सकती हैं, जिनका असर पूरे सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है। इसके अलावा, कोड में जानबूझकर गड़बड़ी या सुरक्षा संबंधी कमजोरी छोड़े जाने की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इंजीनियरों को केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि एआई ने कोड तैयार कर दिया है, बल्कि उन्हें यह भी जांचना होगा कि कोड निर्धारित जरूरतों के अनुरूप है या नहीं, उसमें कोई सुरक्षा जोखिम तो नहीं है और वह वास्तविक परिस्थितियों में सही तरीके से काम करेगा या नहीं। गोपालकृष्णन ने कहा कि भविष्य में प्रोग्रामर की भूमिका में कोड की समीक्षा और प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए इंजीनियरों को एआई से तैयार कोड की गुणवत्ता जांचने, संभावित त्रुटियों की पहचान करने, सुरक्षा संबंधी कमजोरियों को पकड़ने और उसकी विश्वसनीयता प्रमाणित करने का प्रशिक्षण देना होगा। यह बदलाव तकनीकी शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण के तरीकों को भी प्रभावित करेगा। इंजीनियरों को अब केवल प्रोग्रामिंग भाषाओं और कोड लिखने की तकनीक सीखने के साथ-साथ एआई के काम करने के तरीके, उसकी सीमाओं और उसके परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। इस बदलाव के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां भी सामने आएंगी। एआई द्वारा तैयार कोड को जांचने के लिए उन्हें यह समझना होगा कि किसी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, वह किस प्रकार के डेटा का इस्तेमाल कर रहा है और उसमें संभावित जोखिम कहां मौजूद हैं। इसके साथ ही कोड की कार्यक्षमता, उसकी गति, सुरक्षा और लंबे समय तक उपयोग की विश्वसनीयता का परीक्षण करना भी जरूरी होगा। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई से तैयार समाधान केवल देखने में सही न हो, बल्कि वास्तविक उपयोग के दौरान भी अपेक्षित परिणाम दे। इस तरह भविष्य का इंजीनियर केवल कोड लिखने वाला पेशेवर नहीं, बल्कि तकनीकी समाधान का मूल्यांकन करने वाला विशेषज्ञ भी होगा। गोपालकृष्णन ने आईटी सेवाओं और आउटसोर्सिंग क्षेत्र के भविष्य को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि एआई के तेजी से विस्तार के बावजूद बड़ी कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं और आउटसोर्सिंग की मांग बनी रहेगी। हालांकि, इन सेवाओं का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहेगा। कंपनियां अब केवल कर्मचारियों की संख्या या कोड लिखने की क्षमता के आधार पर सेवाएं नहीं लेंगी, बल्कि उन्हें ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत होगी, जो एआई आधारित प्रणालियों को समझ सकें, उनके परिणामों की जांच कर सकें और तकनीकी समाधान को भरोसेमंद बना सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की जनसंपर्क की अभिनव पहल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल बुधवार, 18 नवंबर से शुक्रवार, 20 नवंबर तक दुर्गम जनजातीय क्षेत्र गरबाड़ा तहसील के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहेंगे। मृदु और मितभाषी, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले मुख्यमंत्री के रूप में जनमानस में अपनी विशिष्ट लोकप्रिय छवि बनाने वाले सहज, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री भूपेंद्र पटेल ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निवारण करने के अपने प्रयासों से अब 'हमारे भूपेंद्रभाई' की पहचान भी बनाई है।

मुख्यमंत्री ने अपनी ऐसी ही सहजता और सरलता का एक और परिचय देते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और आदिवासी ग्रामीणों के साथ बैठकर संवाद और जनसंपर्क का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गांवों के सामान्य लोगों के जनजीवन और ग्रामीण जीवन के रहन-सहन को आत्मीयता के साथ निकट से समझने और देखने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के संवेदनशील और जनाभिमुख दृष्टिकोण के साथ इस तीन दिवसीय दौरे का आयोजन किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अपने इस पूरे दौरे के दौरान तीनों दिन अदने आदिवासी परिवारों के घर जाकर उनके साथ बैठकर परंपरागत आदिवासी भोजन और रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही, वे स्थानीय आदिवासी भजन मंडलियों के भजन कीर्तन का श्रवण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री जनजातीय क्षेत्र के 72 घंटे के दौरे के दौरान धानपुर तहसील में जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे आदिवासियों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र बाबा धोड़ाजा देव मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना भी करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अपने तीन दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में स्मार्ट सिटी दाहोद की सरकारी लाइब्रेरी भी जाएंगे, जहां वे बच्चों और युवाओं के साथ संवाद गोष्ठी करेंगे और शुक्रवार, 20 नवंबर को दोपहर बाद गांधीनगर लौटेंगे।

उधना रेलवे मॉडल: अस्थायी इंतजामों से स्थायी समाधान तक का सफर

सूरत में रहने वाले हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए उधना रेलवे स्टेशन बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अपने घरों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यहां यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इससे स्टेशन के होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और आने-जाने के रास्तों पर दबाव बढ़ जाता है।





▸▸पहले भी यात्रियों की अधिक संख्या के कारण भीड़भाड़ की समस्या सामने आती रही है। बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाना जरूरी था, लेकिन यात्रियों के ट्रेन में सवार होने से पहले उनकी व्यवस्था करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अस्थायी होल्डिंग एरिया से तत्काल राहत मिली, लेकिन बड़ी संख्या में यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए स्थायी सुविधा की जरूरत महसूस की गई।

▸▸इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उधना में यात्री सुविधा केंद्र विकसित किया गया, ताकि यात्रियों की आवाजाही और उनके ठहरने की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

योजना से स्थायी सुविधा तक

▸▸मानसून और मिट्टी से जुड़ी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इस केंद्र का निर्माण लगभग पांच महीने में पूरा किया गया और 31 अक्टूबर 2026 को इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया।

▸▸10,224 वर्ग मीटर में फैले इस केंद्र में एक समय में लगभग 15,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। पश्चिम रेलवे के अनुसार, यह अपनी तरह का भारतीय रेल का सबसे बड़ा यात्री होल्डिंग एरिया है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर पहले से मौजूद 2,550 वर्ग मीटर का होल्डिंग एरिया भी यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

▸▸इस विकास के साथ स्टेशन पर यात्रियों के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले उनकी आवाजाही को व्यवस्थित करने की एक विशेष व्यवस्था तैयार हुई है।

प्रतीक्षा और बोर्डिंग की नई व्यवस्था

▸▸यात्री सुविधा केंद्र में टिकट लेने से पहले, टिकट लेने के दौरान और टिकट लेने के बाद के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। यात्री टिकट संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्धारित होल्डिंग एरिया में प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर अपनी ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ सकते हैं।

▸▸इस व्यवस्था से व्यस्त समय में यात्रियों की आवाजाही को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और प्लेटफॉर्म तथा स्टेशन के प्रवेश मार्गों पर भीड़भाड़ का दबाव कम करने में मदद मिलती है।

▸▸केंद्र में 10 टिकट काउंटर, ढके हुए होल्डिंग एरिया, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था, अलग-अलग शौचालय, शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए विशेष कक्ष और आरओ से।

जूनागढ़ परिक्रमा मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु जूनागढ़-राजकोट के बीच चलेंगी 2 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा जूनागढ़ में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध परिक्रमा मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए जूनागढ़ एवं राजकोट के बीच 2 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09604/09603 राजकोट-जूनागढ़-राजकोट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09604 राजकोट-जूनागढ़ स्पेशल ट्रेन राजकोट से सुबह 10:25 बजे प्रस्थान कर दोपहर 13:00 बजे जूनागढ़ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09603 जूनागढ़-राजकोट स्पेशल ट्रेन जूनागढ़ से दोपहर 13:40 बजे प्रस्थान कर शाम 17:05 बजे राजकोट पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भक्तिनगर, गोंडल, गोमटा, वीरपुर, नवागढ़, जेतलसर एवं वडाल स्टेशनों पर ठहरेगी। यह ट्रेन 18 से 26 नवंबर 2026 तक (20 एवं 24 नवंबर को छोड़कर) प्रतिदिन संचालित होगी।

2. ट्रेन संख्या 09606/09605 राजकोट-जूनागढ़-राजकोट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09606 राजकोट-जूनागढ़ स्पेशल ट्रेन राजकोट से रात्रि 23:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि 02:45 बजे जूनागढ़ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09605 जूनागढ़-राजकोट स्पेशल ट्रेन जूनागढ़ से सुबह 04:25 बजे प्रस्थान कर सुबह 06:55 बजे राजकोट पहुंचेगी।

यह ट्रेन भी दोनों दिशाओं में भक्तिनगर, गोंडल, गोमटा, वीरपुर, नवागढ़, जेतलसर एवं वडाल स्टेशनों पर ठहरेगी। यह ट्रेन 18 से 26 नवंबर 2026 तक (19 एवं 23 नवंबर को छोड़कर) प्रतिदिन संचालित होगी।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर, श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में यात्रियों को बेहतर एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत यह व्यवस्था की गई है।

उल्लेखनीय है कि यात्रियों की सुविधा के लिए उपरोक्त दोनों जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें पूर्णतः अनारक्षित रहेंगी। इन ट्रेनों के ठहराव, समय-सारणी एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए यात्री भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अथवा NTES ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



State Action Plan for Containment of Antimicrobial Resistance GUJARAT
Preserve Antibiotics | Protect Lives
सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन



विश्व एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह
(18-24 नवंबर 2026)

एंटीबायोटिक्स का गलत उपयोग,
बढ़ाए सुपरबग्स का प्रकोप

कोविड जितने ही खतरनाक हैं सुपरबग्स

आइए, एंटीबायोटिक्स को बेअसर होने से बचाएँ।

डॉक्टर के परामर्श के बिना एंटीबायोटिक्स न लें और उपचार के दौरान दवाएँ बीच में बंद न करें और निर्धारित कोर्स पूरा करें।
-हर्ष संघवी, उपमुख्यमंत्री, गुजरात

एंटीबायोटिक्स का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। बेहतर महसूस होने पर भी दवाएँ अपने आप बंद न करें और डॉक्टर के निर्देशानुसार पूरा कोर्स करें।
-प्रफुल पानशेरिया, स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात सरकार